

प्रति,

उप संचालक,
बफर जोन वनमण्डल,
कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, म0प्र0।

विषय:— मण्डला जिले के ग्राम हरटोला एवं भिमौरी के बीच अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु 1.61 हेक्टेयर वन भूमि पुलिस अधीक्षक, मण्डला को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:— क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला का पत्र क्रमांक/मा0चि0/1280 दिनांक 30.05.2020

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार मण्डला जिला नक्सल प्रभावित (LWE) में होने के कारण 05 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) for the 1.61 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- प्रकरण में कोई वृक्ष नहीं काटे जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 100 वृक्षों की राशि 2000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि रु. 2,00,000/- कैम्पा मद में जमा कराई जावे।
- 5- User agency shall restrict the no felling of trees.

-2-

- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- 7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 8- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 9- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 10- No labour camp shall be established on the forest land.
- 11- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 13- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 14- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 15- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं एन.पी.व्ही. तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावें। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

02/09/2020
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/949/2020/10-11/2907

भोपाल, दिनांक ~~02/09/2020~~

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला मध्यप्रदेश।
 2. पुलिस अधीक्षक, मण्डला, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/09/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल